वर्ष 13 • अंक 32 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 25 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 2

दूरसंचार फर्मों की आपात योजना तैयार

नंदन नीलेकणी पृष्ठ 3

यूएस एसईसी से इन्फोसिस को मिली क्लीनचिट

डॉलर रु. 76.10 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 82.50 ▲ 1.10 रुपये | सोना (10ग्राम) रु. 42078 ▲ 1522 रुपये | सेंसेक्स 26674.00 ▲ 692.80 | निफ्टी 7801.00 ▲ 190.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 7853.80 ▲ 52.80 | ब्रेंट क्रूड 27.10 डॉलर ▲ 0.70 डॉलर

इक्कीस दिन के लिए बंद हुआ देश

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च

- लॉकडाउन में हर जिला, गांव, मोहल्ला, गली पूरी तरह बंद
- संक्रमण चक्र तोड़ने को 21 दिन अलग रहना जरूरी
- आर्थिक नुकसान होगा मगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी
- कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के पूरे प्रयास
- लोगों को अफवाहों और अंधविश्वास से बचने की राय
- डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवा न लेने की ताकीद

समूचा भारत अगले 21 दिन तक पूरी तरह बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देर शाम देश के नाम संदेश में कहा कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात 12 बजे से देश का हरेक जिला, गांव, गली-मोहल्ला पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से कर्फ्यू ही होगा, लेकिन कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा करना ही होगा। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। इस रकम से कोरानावायरस जांच सुविधा, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा परिधान, उपकरण, सघन चिकित्सा कक्ष शैया, वेंटिलेंटर आदि का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे पहले 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जिसे कुछ स्थानों पर 23 मार्च सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। बाद में दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत कई जिलों में बंदी यानी लॉकडाउन आगे तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री की आज की घोषणा के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा सभी देशवासियों को 21 दिन तक घरों में ही रहना होगा।

मोदी ने कहा, 'बेहद विकसित देश भी इस बीमारी के सामने बेबस साबित हुए। उन देशों का अनुभव बताता है कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण चक्र को तोड़ना ही होगा। चक्र को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक-दूसरे से दूर रहना ही इकलौता उपाय है। उन देशों में लोगों ने सरकार के निर्देशों को माना और हफ्तों घरों से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद स्थिति सुधरने लगी है।'

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इस वायरस से संक्रमण के लक्षण कई दिन बाद दिखते हैं और तब तक संक्रमण कई लोगों में फैल चुका होता है। इसीलिए 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक घरों में बंद रहने से संक्रमण का चक्र तोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'यदि 21 दिन नहीं संभले तो देश और परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कई परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। इसलिए तीन हफ्ते के इस लॉकडाउन का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए। 21 दिन तक भूल जाएं कि घर से बाहर निकलना क्या होता है और घर के भीतर ही रहें। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि देश में जो जहां है वहीं रुक जाए।'

मोदी ने कहा कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। वे प्रयास कर रहे हैं और उनके पास संसाधन भी हैं, लेकिन वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि प्रयासों के बाद भी विपदा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद मामलों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लगे, लेकिन 1 से 2 लाख होने में केवल 11 दिन लगे और अगले 4 दिन में आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। चीन, अमेरिका, इटली, कनाडा, स्पेन जैसे देशों की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकीं। इसलिए बचने का इकलौता रास्ता यही है कि घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लें और उसे तीन हफ्ते तक बिल्कुल नहीं लांघें।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई की देश को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन देश को बचाने के लिए यह कीमत अदा की जाएगी मगर देशवासियों की जान खतरे में नहीं पड़ने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सामान्य बनाने का प्रयास रहा, उसी तरह अगले 21 दिन तक भी आपूर्ति जारी रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बात की गई है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं ही रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए निजी क्षेत्र भी सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी पैथोलॉजी लैब और अस्पताल इस लड़ाई में देश और जनता के साथ हैं और कई कंपनियां भी मदद कर रही हैं। उन्होंने जनता से डॉक्टर, नर्स, अर्द्ध चिकित्साकर्मी, पैथोलॉजिस्ट, वार्ड बॉय, एंबुलेंस चालक, सफाई कर्मी, मीडियाकर्मी, पुलिस बल का सहयोग करने के लिए कहा क्योंकि वे लोगों की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

इस बीच एनएसई ने कहा कि बंदी के बावजूद बुधवार को शेयर बाजार खुले रहेंगे।

एक नज़र

सैनिटाइजर और वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक

सरकार ने देश में कोरोनावायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंगलवार को सभी तरह के सैनिटाइजर और वेंटिलेटर के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह कुछ तरह के वेंटिलेटर, सर्जिकल और डिस्पोजेबल मास्क तथा मास्क बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का निर्यात बंद कर दिया था। कोरोनावायरस के कारण देश में इन उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई है।

टोक्यो ओलिंपिक खेल 2021 तक स्थगित

दुनिया के कई देशों में कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल होने वाले ओलिंपिक खेलों को अगले साल की गर्मियों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खेल महाकुंभ का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होना था लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाख और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद इसे टालने का फैसला किया गया। यह पहला मौका है जब ओलिंपिक को शांतिकाल में स्थगित किया गया है। कई देशों ने इसे स्थगित करने की मांग की थी।

चीन में कोरोनावायरस के बाद अब हंटा का प्रकोप

दुनिया अभी तक कोरोनावायरस के प्रकोप से उबर नहीं पाई है और चीन में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि देश के दक्षिणपश्चिम युन्नान प्रांत में एक व्यक्ति की हंटा वायरस के कारण मौत हो गई। संक्रमित व्यक्ति सोमवार को पूर्वी शानडोंग प्रांत से काम से लौट रहा था और इस दौरान उसकी चार्टर्ड बस में मौत हो गई। बस में सवार अन्य 32 लोगों की जांच की गई है। यह बीमारी चूहों से फैलती है।

टिकट रद्द कराए बिना खुद-ब-खुद मिलेगा रिफंड

आईआरसीटीसी ने कहा है कि जिन यात्रियों ने रद्द की गई ट्रेनों का टिकट ऑनलाइन बुक किया था, उन्हें इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है और उनका पैसा खुद ब खुद वापस मिल जाएगा। इससे पहले रेलवे ने काउंटर से लिए टिकटों को रद्द करने की तीन महीने की समयसीमा बढ़ाकर 21 जून कर दी थी। रेलवे की सहयोगी कंपनी आईआरसीटीसी ने एक बयान में यह जानकारी दी कि अगर यात्री टिकट रद्द करता है तो उसे कम रिफंड मिल सकता है। इसलिए उन्हें टिकट रद्द नहीं करना चाहिए।

आज का सवाल

क्या कोरोना जैसे संकट से निपटने में पर्याप्त हैं देश में स्वास्थ्य सेवाएं

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या रुपये में कमजोरी से सरकारी खजाने पर पड़ेगा असर?	हां	83.33%
	नहीं	16.67%

चढ़ते गिरते बाजार में उथल-पुथल बढ़ी

समी मोडक
मुंबई, 24 मार्च

- वित्त मंत्री से बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिलने से निवेशक निराश
- सेंसेक्स और निफ्टी ने गंवाई शुरुआती बढ़त
- इंडिया वीआईएक्स सूचकांक रिकॉर्ड 86.63 पर पहुंचा

भारतीय शेयर बाजार आज 3.5 फीसदी चढ़ा जबकि दुनिया के अन्य बाजारों में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में तेजी आई। दिन के कारोबार में सेंसेक्स करीब 6 फीसदी चढ़ गया था लेकिन अंतिम घंटे में उसने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी। दरअसल बाजार को भारी भरकम राहत पैकेज की उम्मीद थी लेकिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत उपायों से निवेशकों को निराशा हुई।

कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 693 अंक चढ़कर 26,674 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 191 अंकों की तेजी के साथ 7,801 पर बंद हुआ। इस बीच कुछ एशियाई बाजारों में 7 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रव्यापी बंद और कुछ राज्यों में पर कर्फ्यू की वजह एक दिन पहले बाजार में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। बाजार में उतार-चढ़ाव को आंकने वाला इंडिया वीआईएक्स सूचकांक आज 86.63 पर पहुंच गया, जो नवंबर 2008 के ऐतिहासिक उच्च स्तर 85.13 से ऊपर पहुंच गया है। ब्रोकरेज के अनुसार बाजार में जब तक तीव्र उतार-चढ़ाव नरम नहीं पड़ता है तब तक निचले स्तर का अनुमान लगाना कठिन होगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, 'बाजार के शांत पड़ने से पहले उतार-चढ़ाव को कम होना होगा। 2008, 2011, 2015 और 2018 में भी बाजार के निचले स्तर पर पहुंचने से पहले शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव बना हुआ था।' बाजार के भागीदारों का कहना है कि इतना अधिक उतार-चढ़ाव से संकेत मिलता है कि बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में है। (शेष पृष्ठ 3)

बॉन्ड बाजार में गायब हुए खरीदार-बिकवाल

अनूप रॉय
मुंबई, 24 मार्च

- शुरुआती 30 मिनट में बॉन्ड बाजार में नहीं हुआ कारोबार
- बाजार कर रहा है दरों में तत्काल कटौती का इंतजार

देश के बॉन्ड बाजार में आज शुरुआती 30 मिनट कोई कारोबार नहीं हुआ। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एनडीएस-ओएम पर कुल 7,210 करोड़ रुपये के सौदे हुए। यह सामान्य कारोबार के आधे से भी कम है लेकिन अनुमान से बेहतर निकला। दोपहर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आर्थिक सुस्ती को निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। तब जाकर बॉन्ड बाजार में कारोबार ने गति पकड़ी। इसके अलावा आरबीआई ने द्वितीयक बाजार से 15,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड की खरीदारी की जिससे बाजार की धारणा मजबूत हुई।

10 साल परिपक्वता अवधि का बेंचमार्क बॉन्ड में 1,325 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और इसका सर्वाधिक कारोबार हुआ। बाजार दरों में कम से कम 50 आधार अंक की कटौती की उम्मीद कर रहा है और उद्योग संगठनों ने कम से कम 150 आधार अंक की कटौती की मांग कर रहे हैं। देश और दुनिया में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप से आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मौजूदा सुस्ती के कारण इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 3.5 फीसदी रह सकती है। बॉन्ड डीलरों का कहना है कि कम कारोबार के कई कारण हैं। फर्स्ट रैंड बैंक में ट्रेजरी प्रमुख हरिहर कृष्णमूर्ति ने कहा कि कारोबारी घर से काम कर रहे थे, यानी वे अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए कम से कम कारोबार कर रहे थे।

संकटग्रस्त कंपनियों को सरकार का मरहम

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 24 मार्च

- कर्ज लौटाने में चूक की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई
- विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून
- टीडीएस जमा करने में देरी के लिए दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया
- 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ी
- देरी से भुगतान के लिए ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत की

सरकार ने देश में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच दिवालिया होने के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त कंपनियों को राहत दी है। इन कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्ज लौटाने में चूक की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीडिया से कहा कि अगर यह मुश्किल दौर आगे भी बना रहता है तो सरकार दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के प्रावधान को छह महीने की अवधि के लिए रोकने पर विचार करेगी। इसका मतलब है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 7, 9 और 10 के कार्यान्वयन पर रोक लग जाएगी। इन धाराओं के तहत वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार या प्रवर्तक को किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर केआर शेखर ने कहा, 'इससे अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बाद कंपनियों को अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में आर्थिक पैकेज लेकर आएगी जिससे मुश्किल दौर में मांग और विकास को बढ़ावा मिलेगी।'

सरकार ने साथ ही कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 के क्रियान्वयन को एक साल आगे बढ़ा दिया है। अब यह 2020-21 में लागू होगा। एसआर बाटलीबॉय ऐंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर संजीव सिंघल ने कहा, 'देशव्यापी बंदी को देखते हुए उद्योग और ऑडिट पेशेवर 31 मार्च, 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग निर्देशों की उम्मीद कर रहे हैं।'

वित्त मंत्री ने साथ ही कंपनियों को अनुपालन पर राहत देते हुए विभिन्न तरह की फाइलिंग की समयसीमा बढ़ा दी। नई कंपनियों को कारोबार शुरू करने के बारे में जानकारी देने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर किसी कंपनी के निदेशक ने भारत में कम से कम 182 दिन रहने की शर्त को पूरा नहीं किया है तो इसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों की आपूर्ति भी पड़ी ठप!

पीरजादा अबरार और समरीन अहमद
बेंगलुरु, 24 मार्च

- पुलिस की कार्रवाई से डिलिवरी वाहनों का आवागमन प्रभावित
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी अवरोध
- ई-कॉमर्स और होम डिलिवरी आवश्यक सेवाओं में आने के बावजूद हो रही है दिक्कत

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों और शहरों में बंद से देश भर में ई-कॉमर्स कारोबार लगभग थम गया है। इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और अंतरराज्यीय आवाजाही रोक दी गई है। इससे फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, ग्रोफर्स और मिल्कबास्केट जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिये आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक स्विगी और जोमैटो जैसी खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनियों को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ई-कॉमर्स उद्योग के कार्याधिकारी ने कहा, 'बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। प्रशासन नए-नए नियमों के लिए परिपत्र जारी कर रहा है, जो पहले के परिपत्रों के एकदम उलट हैं।' उन्होंने कहा, 'यह ठीक से संवाद न होने का भी मसला है।'

ई-कॉमर्स कंपनियों को चावल, गेहूं, दाल, बेबी फूड, दूध एवं डेयरी उत्पाद और फल एवं सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अन्य अहम वस्तुओं में साबुन, सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर और मास्क जैसे साफ-स्वच्छता के उत्पाद शामिल हैं।

ई-कॉमर्स उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि इस समय बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे लोगों को पावर बैंक, लैपटॉप, राउटर, हेडसेट, टैबलेट और कुर्सी जैसी चीजों की आपूर्ति करने में दिक्कतें आ रही हैं, जबकि इन चीजों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। ई-कॉमर्स क्षेत्र की इन चुनौतियों पर ध्यान देते हुए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किया कि ई-कॉमर्स और होम डिलिवरी आवश्यक सेवाओं में आती हैं और इन्हें उन पाबंदियों से बाहर रखा जाना चाहिए, जो कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई हैं। महाराष्ट्र ने भी एक आदेश जारी करते हुए कहा कि दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स सेवाओं को पाबंदियों से बाहर रखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं समेत अन्य ई-कॉमर्स श्रेणियों की बिक्री में कम से कम 60 फीसदी गिरावट आई है। बहुत से उपभोक्ताओं ने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर कहा है कि उन तक ग्रोफर्स, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स ऐप की डिलिवरी नहीं पहुंच रही है। लोकलसर्किल के एक सर्वेक्षण के मुताबिक बंद की वजह से करीब 35 फीसदी ग्राहकों को ई-कॉमर्स ऐप के जरिये आवश्यक सामान नहीं मिल पाया। करीब 17 फीसदी उपभोक्ताओं को खुदरा स्टोरों से आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पाईं। लोकलसर्किल्स ने कहा, 'राज्य प्रशासन को शीर्ष पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए संवदेनशील बनाना चाहिए कि जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की थोक एवं खुदरा स्टोरों और लोगों के घरों में आपूर्ति में अवरोध पैदा न करें।'

रोजाना किराने का सामान डिलिवर करने वाली गुरुग्राम की कंपनी मिल्कबास्केट ने कहा कि स्थानीय पुलिस कंपनी के कर्मचारियों, वेंडरों और वाहनों को सड़कों पर चलने नहीं दे रही है, जिससे उसका परिचालन प्रभावित हो रहा है। कंपनी ने सोमवार को कहा, 'कल हमें हजारों ऑर्डर रद्द करने पड़े। हम गुरुग्राम में केवल 40 फीसदी ऑर्डर पूरे कर पाए। नोएडा में और भी कम ऑर्डर पूरे हो पाए। हमें आज पूरे ऑर्डर रद्द करने पड़ सकते हैं, जिसका चार शहरों में डेढ़ लाख परिवारों पर असर पड़ेगा।'

खबरों में रहे स्टॉक

डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज

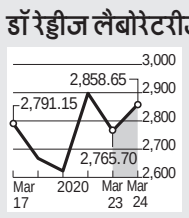

वाणिज्यिक पत्र के जरिये रकम जुटाने पर विचार के लिए बोर्ड बैठक 27 मार्च को

₹ 2,765.70 पिछला बंद भाव
₹ 2,858.65 आज का बंद भाव
▲ 3.36 %

इन्फोसिस

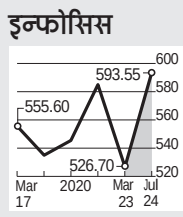

यूएस एसईसी ने व्हिसलब्लोअर मामला खत्म किया

₹ 526.70 पिछला बंद भाव
₹ 593.55 आज का बंद भाव
▲ 12.69 %

हिंदुस्तान यूनिलीवर

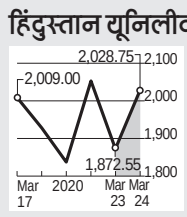

ग्लेनमार्क से वीवॉश का अधिग्रहण किया

₹ 1,872.55 पिछला बंद भाव
₹ 2,028.75 आज का बंद भाव
▲ 8.34 %

टीटीके प्रेस्टिज

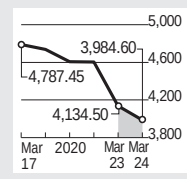

31 मार्च तक विनिर्माण संयंत्र को बंद रखने का निर्णय लिया

₹ 4,134.50 पिछला बंद भाव
₹ 3,984.60 आज का बंद भाव
▼ 3.63 %

एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज

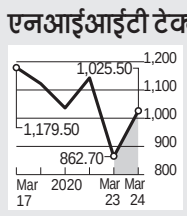

ए समूह में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 862.70 पिछला बंद भाव
₹ 1,025.50 आज का बंद भाव
▲ 18.88 %

संक्षेप में

कोरोना संकट : जेके टायर के अधिकारी लेंगे कम वेतन

कोरोनावायरस संकट के बीच जे.के. टायर ऐंड इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी 25 फीसदी तक कम वेतन लेंगे। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रघुपति सिंघानिया ने एक बयान में कहा, कोरोनावायरस संकट की वजह से मौजूदा वक्त में हम बिक्री और लाभ दोनों स्तर पर अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सहृदयता दिखाते हुए हमारा प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी आगे आए हैं और उन्होंने अपना 25 फीसदी तक कम वेतन लेने का निर्णय किया है। वेतन में यह कटौती कंपनी के वैश्विक परिचालन के अधिकारियों पर भी लागू होगी। *भाषा*

एमेजॉन ने गैर-जरूरी सामान की बिक्री बंद की

एमेजॉन ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में कम प्राथमिकता वाले उत्पादों की ऑर्डर अस्थायी तौर पर निलंबित कर रही है। ऐसे उत्पादों के लिए कंपनी अपने ग्राहकों को ऑर्डर रद्द करने का विकल्प दे रही है और उसके लिए रिफंड देने को तैयार है। सभी शहरों में लॉकडाउन के कारण एमेजॉन स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है ताकि प्राथमिकता वाले सामान ग्राहकों के पास बिना किसी अवरोध के सुरक्षित पहुंचे। *बीएस*

दूरसंचार फर्मों की आपात योजना तैयार

आपात योजना के जरिये कंपनी के अहम नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, कॉल सेंटर को अलग-थलग किए जाने के दौरान निपटा जा सकता है

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 24 मार्च

दूरसंचार कंपनियां कोविड-19 से अलग अप्रत्याशित चुनौती से जूझ रही हैं। यह संकट है जो भारतीय कंपनी जगत को इंटरनेट की अबाध सेवा मुहैया कराना क्योंकि वे घर बैठकर दफ्तर संभाल रहे हैं।

मौजूदा क्षमता पर ये चीजें उपलब्ध कराने के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कंपनियों ने जरूरी जोखिम में कमी वाले प्रोटोकॉल के साथ विस्तृत महामारी रिस्पांस प्लान चालू किया है, वहीं यह सुनिश्चित कर रही है कि नेटवर्क को चालू रखने के लिए मिशन क्रिटिकल प्रॉसेस जारी रहे क्योंकि दूरसंचार आवश्यक सेवा है।

समझा जाता है कि एयरटेल के पास पूरी तरह से तैयार आपात योजना है, जिसके जरिये कंपनी के अहम नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, कॉल सेंटर को अलग-थलग किए जाने के दौरान निपटा जा सकता है।

कंपनी ने हर लोकेशन को डिस्ट्रिब्यूटेड व वर्चुअल दोनों तरीके से परिचालित करने में सक्षम बनाया है। हर टीम को दो में बांटा गया है ताकि एक साइट पर कम लोग रहें और कार्यस्थल सुरक्षित बनाया जा सके।

कंपनी ने दूसरे लोकेशन से नेटवर्क की निगरानी व प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू की है ताकि अगर कुछ समय तक किसी इलाके में पहुंचना संभव न हो तो यह कारगर रहे। साथ ही कंपनी ने सुरक्षित कनेक्शन के साथ कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाया है। भारती एयरटेल के सीटीओ रणदीप सेखन ने कहा, एयरटेल का नेटवर्क बीसीपी (बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग) मोड में है और किसी आपात स्थिति में सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे मोबाइल, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, डीटीएच और फाइबर नेटवर्क उभरते परिदृश्य में ग्राहकों को सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्होंने कहा, सभी ऑपरेशन ठीक तरह से चालू हैं और 80 फीसदी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं।

वोडाफोन आइडिया के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, संकट के दौरान आवश्यक सेवा के तौर पर दूरसंचार नेटवर्क के अबाध परिचालन के लिए हम सरकारी निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, वोडाफोन आइडिया के पास काम की लचीली नीतियां हैं, जो काम के घंटे तय करने, घर से काम करने और संगठन के भीतर अलग लोकेशन से काम करने में सक्षम बनाता है। यह हमें मौजूदा स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया जताने की इजाजत देता है और यह काम अपने वर्कफोर्स को वैकल्पिक तरीका अपनाने में सक्षम बनाकर होता है। हमारे ज्यादातर कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। कंपनी अपने सभी ऑपरेशन में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान की समीक्षा भी कर रही है।

दूरसंचार की तैयारी

■ कंपनियों ने जरूरी जोखिम में कमी वाले प्रोटोकॉल के साथ विस्तृत महामारी रिस्पांस प्लान चालू किया है, वहीं सुनिश्चित कर रही है कि नेटवर्क को चालू रखने के लिए मिशन क्रिटिकल प्रॉसेस जारी रहे क्योंकि दूरसंचार आवश्यक सेवा है

बीएस-4 के लिए सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद

ज्योति मुकुल और शैली सेठ मोहिले
नई दिल्ली/मुंबई, 24 मार्च

देश भर में 1 अप्रैल से केवल नए उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री करने का निर्देश है लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलने के कारण पुराने उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री के लिए समय-सीमा में कोई भी विस्तार सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही कोई निर्णय लेगी।

वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) और हीरो मोटोकॉर्प एवं होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर्स इंडिया सहित दोपहिया विनिर्माताओं ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर बीएस-4 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री के लिए समय-सीमा में विस्तार देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के कारण वाहन कंपनियां इस महीने के अंत तक अपने बीएस-4 वाहनों को खपाने में असमर्थ हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अभी बाकी है। डीलरों ने उम्मीद जताई है कि उनकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में इसी सप्ताह सुनवाई होगी लेकिन सूत्रों का कहना है कि 31 मार्च से पहले सुनवाई की संभावना नहीं दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च को इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सुनवाई को टालने और केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

फरवरी के आरंभ में भी न्यायाल ने इस समय-सीमा में विस्तार दिए जाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद फाडा ने वाहन डीलरों को 31 मार्च 2020 से पहले बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को खपाने के लिए कहा था। दोपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों के बचे स्टॉक को इस महीने के अंत तक खपाने की समय-सीमा में कोरोनावायरस प्रकोप के मद्देनजर विस्तार दिए जाने की किसी भी योजना का विरोध किया है।

बढ़ते डेटा इस्तेमाल से ऑपरेटर दबाव में

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 24 मार्च

रविवार से दूरसंचार ट्रैफिक में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की वह से ऑपरेटर अब सरकार से अस्थायी तौर पर तुरंत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रयास से उन्हें डेटा इस्तेमाल में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोनावायरस के तेज प्रसार की वजह से 'वर्क फ्रॉम होम' और लोगों के 'सेल्फ क्वारंटाइन' यानी घरों में ही रहने से डेटा इस्तेमाल में भारी इजाफा हुआ है।

एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किए जाने के बाद हमने रविवार को घने इलाकों में डेटा इस्तेमाल में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की। उसके बाद से इसमें लगातार इजाफा हुआ है। सीओएआई द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह डेटा ट्रैफिक 10 प्रतिशत बढ़ा।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेजे पत्र में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने अल्पावधि और अस्थायी तौर पर 'एक्सेस एवं बैकहॉल माइक्रोवेव' दोनों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की मांग की है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों को तेजी से बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि सीओएआई के महानिदेषक राजन मैथ्यू का कहना है कि वे इस संबंध में अभी भी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दूरसंचार संगठन ने दूरसंचार विभाग से टावरों के लिए अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा है।

बोफा ग्लोबल रिसर्च इंडिया के अनुसार, भारत में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की पहुंच सिर्फ 6 प्रतिशत है जिससे वर्क फ्रॉम होम के लिए दूरसंचार ट्रैफिक (जो कुल ट्रैफिक का लगभग 70 प्रतिशत है) का दबाव सेल्युलर नेटवर्क पर पड़ने की आशंका है। भारत में सिर्फ1.9 करोड़ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं जबकि कुल 3जी और 4जी ग्राहकों की संख्या 63 करोड़ है। विश्लेषकों का कहना है कि एयरटेल जैसी कई कंपनियां फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए नए ग्राहकों से कोई इंसटॉलेशन चार्ज या सिक्योरिटी राशि नहीं वसूल रही हैं जबकि एसीटी ने अतिरिक्त शुल्क के बगैर स्पीड बढ़ाकर 300 एमबीपीएस तक कर दी है और बीएसएनएल उन ग्राहकों के लिए एक महीने तक फ्री ब्रॉडबैंड की पेशकश कर रही है जिनके पास उनकी कंपनी का लैंडलाइन कनेक्शन पहले से ही है।

हालांकि सीओएआई से मांग इस तथ्य को देखते हुए उचित दिख रही है कि अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशंस ने एटीऐंडटी, वेरीजॉन, टी-मोबाइल और यूएस सेल्युलर को ज्यादा स्पेक्ट्रम के लिए अस्थायी तौर पहुंच मुहैया कराई है जिससे कि वे लगभग 60 दिन के लिए अपनी वायरलेस क्षमता बढ़ा सकें।

तमिलनाडु की कंपनियों ने रोका उत्पादन

गिरीश बाबू
चेन्नई, 24 मार्च

तमिलनाडु सरकार के निर्देश और कई दिग्गज कंपनियों के अपना परिचालन रोकने की घोषणा के बाद राज्य की विनिर्माण कंपनियों ने भी कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए अपना कामकाज बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने महामारी कानून, 1897 के तहत अधिसूचना जारी करके आज शाम 6 बजे से 1 अप्रैल, 2020 तक राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। टीवीएस ग्रुप की कंपनी सुंदरम फास्टनर्स और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मुरुगप्पा ग्रुप की ईआईडी पैरी, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, जीएचसीएल, पोन्नी शुगर्स, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड और एमएम फॉर्जिंग्स ने आज शाम से अपना कामकाज रोकने की घोषणा की है। ईआईडी पैरी ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि अभी यह पता नहीं है कि कंपनी का कामकाज कब तक बंद रहेगा। कंपनी स्थिति का आकलन कर रही है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार ने विनिर्माण संयंत्रों को कुछ कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित की है और सेवा क्षेत्र में कारोबार पर असर पड़ा है।

वेतन देने में मदद चाहती हैं विमानन फर्में

विमानन कंपनियों का नकदी प्रवाह थम गया है लेकिन तय लागत मसलन विमान पट्टा किराया और कर्मचारियों के वेतन की लागत बरकरार है

अरिदम मजूमदार
नई दिल्ली, 24 मार्च

विमानन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सरकार की मदद मांगी है क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के प्रसार ने अधिकारियों को हवाई परिवहन 31 मार्च तक बंद करने के लिए बाध्य किया है। सूत्रों ने कहा कि विमानन कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार विमानन कंपनियों के कर्मचारियों के तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी हिस्सा वहन करे।

यह मांग सरकार के निर्देश से निकली है, जिसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें, वहीं कंपनी का कामकाज कोरोनावायरस महामारी के कारण थम गया है।

श्रम व रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को नौकरी से न हटाएं खास तौर से आकस्मिक या अनुबंध वाले कर्मचारियों को और न ही उनके वेतन में कटौती करे।

विमानन कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि हमें कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल हो रही है क्योंकि कंपनियां पहले ही काफी कम मार्जिन पर काम कर रही हैं और टिकट बिक्री से मिलने वाले नकदी प्रवाह पर ज्यादातर आश्रित होती है।

विमानन कंपनियों की गुहार

- यह मांग सरकार के निर्देश से निकली है, जिसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें
- विमानन कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि हमें कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल हो रही है
- विमानन कंपनियों को आशंका है कि हवाई परिवाहन पर पाबंदी 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकती है

विमानन कंपनियों को आशंका है कि हवाई परिवहन पर पाबंदी 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकती है और जब यह खुलेगा तो ग्राहकों की मांग कमजोर रहेगी और वे कई विमान खड़े करने पर बाध्य हो जाएंगे। सरकारी आकलन के मुताबिक, भारतीय विमानन कंपनियां अगले दो महीने में अपने बेड़े का महज 30 फीसदी ही परिचालित कर पाएंगी।

एक निजी विमानन कंपनी के अधिकारी के मुताबिक, हवाई परिवहन सरकार के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया। सरकारी लॉकआउट की अवधि में हमारी नकदी प्रवाह शून्य हो गया है, लेकिन तय लागत उतनी ही बनी हुई है। अन्य कारोबार के उलट अगर विमान नहीं उड़ रहे हैं तो भी हमें पट्टा किराया व वेतन चुकाना पड़ेगा। सरकार को कुछ बोझ उटाना चाहिए, अगर वह कारोबार का अस्तित्व बनाए रखना चाहती है।

इंडिगो को छोड़कर भारत की बाकी विमानन कंपनियों के पास लंबे संकट के लिए नकद शेष नहीं है। इंडिगो के सीईओ रोनो दत्ता ने मंगलवार को कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि उड़ान बंद होने के बाद भी वह वेतन का भुगतान करेंगे। सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ऐसी मांग की गई है लेकिन कहा कि सभी कर्मचारियों के वेतन का ध्यान रखना मुश्किल है। इसके बजाय निचले स्तर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैकेज पर काम किया जा सकता है। विमानन कंपनियों के कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा मसलन सिक्योरिटी एजेंट, लोडर, ड्राइवर, ग्राउंड हैंडलर्स अनुबंध पर काम करते हैं और उन्हें डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है।

विमानन कंपनियों के कर्मचारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से अपनी नौकरी के जारी होने को लेकर अपनी बेताबी का जिक्र किया। अगरतला एयरपोर्ट पर चेक इन एजेंट मनोज सैकिया ने कहा, कंपनियां पेरोल वाले स्थायी कर्मचारियों को शायद नहीं निकालेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बाबत निर्देश दिया है, लेकिन हमारे जैसे अनुबंध वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य अनिश्चित है। गोएयर पहले से ही अनुबंध वाले विदेशी पायलटों को मार्च के पहले हफ्ते के बाद से निकालना शुरू कर कर चुकी है। दिल्ली की स्पाइसजेट ने करीब 20 पायलटों के नोटिस अवधि में कमी का फैसला लिया है, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है।

अधिकारी ने कहा, मुश्किल समय की अभी शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि जब पाबंदी हटेगी तो हम पूरी उड़ान देखेंगे। उपभोक्ताओं का भरोसा बहाल होने में कम से कम छह महीने लग सकते हैं। ऐसे में सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की दरकार है।

इन्फोसिस को मिली क्लीनचिट

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 24 मार्च

सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस को व्हिसलब्लोअर मामले मेंअमेरिका के सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से क्लीनचिट मिल गई है। व्हिसलब्लोअर ने इस आईटी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन पर कंपनी के बहीखातों में हेराफेरी कर आंकड़ों को बढ़ाचढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि अमेरिकी बाजार नियामक ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है।

कंपनी ने अपने खुलासे में कहा है, 'कंपनी को अमेरिकी बाजार नियामक से सूचना मिली है कि एसईसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और कंपनी को अब इस मामले में एसईसी द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने की उम्मीद है।' कंपनी ने कहा है, 'कंपनी ने भारतीय नियामकों द्वारा की गई सभी पूछताछ में अपनी प्रतिक्रिया दी है और वह आगे भी कोई सूचना मांगे जाने पर अपना सहयोग जारी रखेगी।'

अक्टूबर 2019 के आखिर में व्हिसलब्लोअर का एक पत्र सार्वजनिक हुआ था जिसमें कंपनी के सीईओ एवं सीएफओ पर कंपनी के बहीखातों में हेराफेरी के जरिये वृद्धि संबंधी आंकड़ों को बढ़ाचढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इन्फोसिस ने अपनी लेखा समिति के जरिये मामले की जांच की। जांच में कंपनी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद पाया गया। इसलिए लेखा समिति ने

- व्हिसलब्लोअर मामले में यूएस एसईसी ने खत्म किया मामला
- गुरुवार को एनएसई पर कंपनी का शेयर 16 फीसदी बढ़त के साथ 600 रुपये पर बंद हुआ

इसी साल जनवरी में कंपनी को हरी झंडी दे दी थी।

इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलकेणि ने आंतरिक जांच में प्रबंध की कोई गलती न पाए जाने पर कहा था, 'हम आश्वस्त है कि हमने इस मामले की काफी गहन और विस्तृत जांच की है जिससे एसईसी के समझ हमारा पक्ष मजबूत होगा।' यूएस एसईसी द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद कंपनी का शेयर एनएसई पर आज 14 फीसदी बढ़त के साथ करीब 600 रुपये पर बंद हुआ।

मुंबई की ब्रोकरेज फर्म शेयरखान के अनुसंधान प्रमुख संजीव होता ने कहा, 'निश्चित तौर पर कंपनी के शेयर पर आज उसका असर दिखा क्योंकि अब उसे एसईसी से क्लीनचिट मिल गई है। इसलिए कोरोनावायरस को लेकर निकट भविष्य की चिंताओं के अलावा कंपनी इस मामले के खत्म होने के बाद उद्योग में बेहतर वृद्धि दर्ज करेगी।' हालांकि होता ने कहा कि अपनी प्रतिस्पर्धियों की तरह बेंगलूरु की इस कंपनी को बड़े सौदे हासिल करने में देरी भी हो सकती है क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलने से ग्राहक विवेकाधीन खर्च में परहेज कर रहे हैं।

आईटी उद्योग अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों में कमजोर मांग से जूझ रही है। इसके अलावा इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी पर जोर दिए जाने के कारण कई कंपनियों को अपने कार्यालय बंद भी करने पड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप आईटी कंपनियों को नए सौदे हासिल करने में कहीं अधिक देरी का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में कहा गया है कि केवल इसी महीने करीब 3 से 4 अरब डॉलर मूल्य के सौदों को टाला जा चुका है।

आर्थिक सुनामी है कोविड-19 नाकाम होंगे कारोबार : मूडीज

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 24 मार्च

मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी ने वैश्विक आर्थिक सुनामी का सृजन किया है क्योंकि इस वायरस का प्रसार काफी तेजी से दुनिया भर के देशों में हुआ है और बंदी (लॉकडाउन) के लिए मजबूर किया है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा, कोविड-19 को लेकर चीन का अनुभव बताता है कि यह बीमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर डाल सकता है।

मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने हालिया रिपोर्ट में कहा है, चीन और एशिया के बड़े हिस्से को इस साल झटका देने वाली आर्थिक सुनामी और कुछ हफ्ते पहले यूरोप को अपने आगोश में लेने वाली सुनामी अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्से में गैर-जरूरी कारोबार बंद करने की जरूरत पड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर अचानक रोक अप्रत्याशित है। इसके समान एकमात्र घटनाक्रम 9/11 आतंकवादी हमला है, लेकिन यह एक या दो दिन में खत्म हो गया और विमानों को छोड़कर बाकी कारोबारों का परिचालन जारी रहा।

कोविड-19 महामारी से पहले एजेंसी ने वैश्विक वास्तविक जीडीपी की रफ्तार साल 2020 में 2.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। एजेंसी ने कहा, चूंकि इस वायरस के कारण अब पर्यटन, व्यापार और कई अन्य कारोबार बंद हो रहे हैं, लिहाजा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर होगा और वास्तविक जीडीपी 0.4 फीसदी घटेगी।

मूडीज ने कहा, और वित्तीय परेशानी होने वाली है क्योंकि छंटनी में इजाफा हुआ है, कारोबारों ने निवेश में कटौती की है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने आक्रामकता के साथ कदम उठाए हैं, लेकिन उनके पास भी इस संकट पर लगाम कसने के लिए हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि ब्याज दर शून्य के आसपास हैं।

उन्होंने कहा, अब पूरी जवाबदेही सरकार पर है कि वह परेशान परिवारों और कारोबारों को तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करे। कोविड-19 ने अंतत: कितनी आर्थिक क्षति पहुंचाई वह वायरस के प्रसार पर निर्भर करेगा और इस पर भी कि सरकार ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया जताई।

मूडीज एनालिटिक्स ने कहा, आर्थिक सूनामी के दूसरे दौर में अन्य आधे परिवारों को झटका देगा, जिनकी परिसंपत्तियों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। तीसरे चरण में कारोबारी निवेश में तेजी से वापसी होगी। कारोबार पहले से ही अमेरिका व चीन के बीच कारोबारी युद्ध, ब्रेक्सिट और अन्य भूराजनैतिक चिंता से जुड़ी लंबी सूची से प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा, कारोबारी दिवालियापन में इजाफा और नाकामी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। यह निवेश में गिरावट में और इजाफा करेगा और भविष्य के आर्थिक सुधार में रुकावट लाएगा।

आयातित लागत से काफी कम पर बिक रहा सोना

उपलब्धता के अभाव में चांदी आयातित लागत से बिक रही मंहगी, कच्चा तेल और धातुओं में तेजी

राजेश भयानी
मुंबई, 24 मार्च

सोने-चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते सराफा बाजार में असामान्य स्थिति बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में आज दोपहर सोने के वायदा का कारोबार 1,653 डॉलर प्रति औंस पर हो रहा था, जो सोमवार के मुकाबले 107 डॉलर प्रति औंस या 6 फीसदी अधिक था। हालांकि देश में एमसीएक्स और मुंबई के हाजिर बाजारों में सोना आयातित कीमत से काफी कम (डिस्काउंट) पर बिक रहा था। वहीं चांदी आयातित लागत से अधिक (प्रीमियम) पर बिक रही थी।

दोनों कीमती धातुओं से संबंधित मुद्दे एक समान हैं, लेकिन दोनों के फंडामेंटल अलग-अलग हैं। चांदी की मांग बढ़ी है, जबकि बाजार में सोने के ग्राहक गायब हो गए हैं। जब 999 शुद्धता के सोने की लागत आयात शुल्क सहित 43,380 रुपये प्रति 10 ग्राम आ रही है। उस समय एमसीएक्स पर सोने का कारोबार 41,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो रहा था। बाद में एमसीएक्स पर सोने की कीमत मामूली गिरावट के साथ 41,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। एमसीएक्स पर सोने का वायदा आयातित लागत से 3.3 फीसदी कम पर था और हाजिर बाजार में कारोबार और अधिक डिस्काउंट पर हो रहा था।

भारतीय समयानुसार शाम पांच बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमत वायदा से कम थी। आईबीजेए के मुताबिक 999 शुद्धता का सोना हाजिर बाजार में 1.2 फीसदी चढ़कर 41,206 रुपये पर बंद हुआ। एमसीएक्स पर सोना वायदा इसलिए भारी डिस्काउंट पर बिक रहा था क्योंकि बिकवाल फंस गए हैं और वे डिलिवरी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि एमसीएक्स पर डिलिवरी होने वाला सोना उपलब्ध नहीं है। एमसीएक्स पर सोने के अप्रैल अनुबंध की डिलिवरी अवधि महीना खत्म होने के बाद शुरू होगी।

केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से कनाडाई बाजारों में सोने और चांदी के दाम आयातित लागत से काफी अधिक बने हुए थे। इसे बहुत से कारोबारी एमसीएक्स और कोमेक्स में अदला-बदली के मौके के रूप देख रहे हैं, जिसमें कारोबारी कोमेक्स (अमेरिका) में बेच रहे थे और एमसीएक्स पर खरीद रहे थे। दोनों के बीच अंतर 1,000 रुपये था। लेकिन नकदी की किल्लत के कारण उनमें से ज्यादातर को सोमवार को अपनी पोजिशन काटनी पड़ीं, जिससे अंतर बढ़कर 2,000-2,200 रुपये तक पहुंच गया।'

सूत्रों ने कहा कि अगर एक्सचेंज के विक्रेताओं को निपटान पर सोने की डिलिवरी करनी पड़ी तो हाजिर बाजारों के बंद होने से उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। एमसीएक्स पर भी सोने की फिजिकल डिलिवरी लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खरीदारों के नाम मालिकाना हक हस्तांतरित किए जाएंगे।

केवल आयातित या एलबीएमए सोने की ही एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर डिलिवरी की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का आना बंद होने के बाद आयात रुक गया है। बाजार में इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर बिकवालों को डिलिवरी देने के लिए बाध्य किया गया तो उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

चांदी आयातित लागत से करीब दो फीसदी अधिक कीमत पर बिक रही है क्योंकि इसका स्टॉक खत्म हो गया है। देश में हाजिर बाजार लगभग बंद हो चुका है, लेकिन कारोबारी मामूली कारोबार के बीच कीमतें जारी कर रहे हैं। भारत में चांदी की मांग है। चांदी के मुकाबले सोने की कीमत में कारोबार करने वाले कारोबारी सोना बेच रहे हैं और चांदी खरीद रहे हैं क्योंकि यह अनुपात शुक्रवार को 123 पर पहुंच गया। बाद में यह अनुपात सोमवार को घटकर 114 पर आ गया, लेकिन सोने की वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद आज बढ़कर 120 पर पहुंच गया। जब अनुपात में गिरावट के आसार होते हैं तो चांदी खरीदी जाती है और सोने की बिकवाली की जाती है।

यहां तक क सोमवार को एमसीएक्स पर कारोबारी सत्र के अंत में सोने में शीर्ष 10 खरीदारों और बिकवालों की पोजिशन इस बात संकेत देती हैं कि उन बिकवालों की सं ?या अधिक हैं, जो वास्तव में हेजर हैं। सोने की 10 शीर्ष बिकवाली की ओपन पोजिशन 17,936 लॉट थीं, जबकि शीर्ष 10 लिवाली पोजिशन 10,940 लॉट थीं। सोने में ओपन इंटरेस्ट लगातार कम हो रहा है। आज दोपहर स्वर्ण वायदा में ओपन इंटरेस्ट 19,145 लॉट था, जो एक पखवाड़े में करीब 20 फीसदी कम हो गया है। चांदी में सबसे अधिक मासिक ओपन इंटरेस्ट 13 मार्च को था, जहां से यह करीब 40 फीसदी गिरकर 5,879 लॉट पर आ गया है।

एमसीएक्स पर चांदी का वायदा शाम पांच बजे 39,858 था। हाजिर बाजार में चांदी 5.8 फीसदी चढ़कर 39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7 फीसदी चढ़ा, जबकि धातुओं में 1-3 फीसदी तेजी आई।

बिगबास्केट की झोली में मिल्क डिलिवरी स्टार्टअप डेलीनिंजा

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 24 मार्च

ऑनलाइन ग्रॉसरी फर्म बिगबास्केट ने मंगलवार को ऑनलाइन डिलिवरी ऐप डेलीनिंजा के 100 फीसदी कारोबार के अधिग्रहण का ऐलान किया। कंपनी ने इस सौदे की वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया। लेकिन कहा कि इस अधिग्रहण से बिगबास्केट बेंगलूरु में सबस्क्रिप्शन डिलिवरी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को एकीकृत कर लेगी।

डेलीनिंजा अभी रोजाना करीब 1.10 लाख ग्राहकों को सेवाएं देती है और यह कंपनी की बीबी डेली एक्टेंसिव नॉन-मिल्क रेंज में इजाफा करेगा।

छोटे कारोबारियों के साथ कारोबार से बिगबास्केट के बिजनेस का एक हिस्सा बढ़ रहा है। डेलीनिंजा के पास अभी मिल्कमैन पार्टनर्स का बड़ा नेटवर्क है। बिगबास्केट के सहसंस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी हरि मेनन ने कहा, यह हमें बीबी डेली के तहत पेशकश का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। प्रमुख राष्ट्रीय ब्रांडों व आपूर्ति श्रृंखला के साथ बने हमारे संबंधों से हमें काफी मदद मिलेगी। हमारा इरादा डिलिवरी में उत्पादकता सुधारने और समय से पहले घाटा समाप्त करने का है।

डेलीनिंजा के सीईओ और सहसंस्थापक सागर यारनलकर ने

कहा, यह अधिग्रहण हमारी टीम के सदस्यों, शेयरधारकों और संस्थापकों के लिए अहम है। उन्होंने कहा, पांच साल पहले जब हमने डेलीनिंजा की शुरुआत की थी तब बिगबास्केट एक कंपनी थी हम जिसका अनुसरण करने की उम्मीद कर रहे थे और अब हम बिगबास्केट परिवार का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं।

कंपनी ने कहा, अभी बीबी डेली हर दिन करीब 1.60 लाख डिलिवरी करता है, जिसमें ताजा फल व सब्जियों, ब्रेड, डेयरी, और अंडों की विस्तृत रेंज शामिल है। यह ब्रेकफास्ट वाले अनाज, नारियल, पर्सनल केयर और बेबी केयर प्रॉडक्ट्स भी उपलब्ध कराता है।

अब बीबी डेली की पहुंच डेलीनिंजा के 2,000 मिल्कमैन पार्टनर्स के नेटवर्क तक हो जाएगी, जो देश भर में फैले हैं।

बीएस बातचीत

कोरोना के प्रसार के बाद हमारे ऑर्डर में दोगुना इजाफा

जब ज्यादातर किराना स्टोर और सुपर मार्केट बंद हैं तो ज्यादातर लोग कोरोनावायरस का प्रसार न्यूनतम करने के लिए अपने-अपने घरों में रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रॉसरी फर्म बिगबास्केट मांग में भारी बढ़ोतरी देख रही है। इससे कंपनी पर काफी दबाव पड़ा है। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ **हरि मेनन** ने **विभु रंजन मिश्रा** को दिए साक्षात्कार में बताया कि बेंगलूरु की कंपनी कैसे भारी मांग का प्रबंधन कर रही है और मुश्किल वक्त में आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित भी कर रही है। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

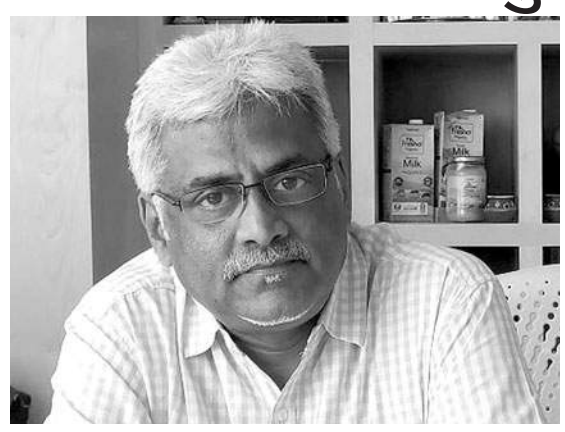

कोरोनावायरस से जुड़े मौजूदा संकट के कारण क्या आपका आपूर्ति नेटवर्क और परिचालन प्रभावित हुआ है?

इस पर असर पड़ा है। क्योंकि हम ऑर्डर में काफी बढ़ोतरी देख रहे हैं। वास्तव में रोजाना के ऑर्डरों की संख्या सामान्य अवधि के मुकाबले दोगुनी हो गई है। ऐसे ऑर्डर का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर रहे हैं लेकिन यह वास्तव में हमारे सिस्टम व लोगों पर भारी दबाव डाल रहा है। मुश्किल समय में जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उन्हें मैं सलाम करता हूं। डिलिवरी सहायक समेत उनमें से कई लोग समझते हैं कि सेवा जारी रखना अभी राष्ट्र की जरूरत है। वास्तव में उनमें से कई खुश थे जब वे एक दिन पहले शाम को सामान की डिलिवरी के लिए निकले।

क्या यह आपके आपूर्ति पक्ष पर दबाव डाल रहा है?

हमारा आपूर्ति पक्ष ठीक तरह से परिचालित हो रहा है। कुल मिलाकर आपूर्ति पक्ष को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि हमें काफी ऑर्डर मिल रहे हैं जिसका प्रबंधन हम अपनी मौजूदा क्षमता में कर सकते हैं, जिनमें मूल रूप से कर्मचारी, वैन और स्टोरेज शामिल है। चूंकि ऑर्डर में भारी इजाफा हो रहा है, ऐसे में डिलिवरी स्लॉट तेजी से बंद हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डर पहले उसी दिन या अगले दिन डिलिवर हो जाते थे उसमें अब 2 या तीन दिन लग रहे हैं। इसके अलावा हमारे ज्यादातर सप्लायर हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्हें अहसास हो रहा है कि कारोबार ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में वे हमें काफी ज्यादा सहयोग दे रहे हैं।

क्या यह आपके कर्मियों पर काफी दबाव डाल रहा है?

वास्तव में हमें उतने लोग नहीं मिल रहे हैं, जितने की दरकार इतने ऑर्डर को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्षमता पर हमारा पूरा नियंत्रण है। ऐसे में हमारे पास रोजाना उपलब्ध कर्मियों व डिलिवरी वैन की संख्या के आधार पर हम उस दिन के लिए क्षमता तय करते हैं। उसके बाद आने वाले ऑर्डर की डिलिवरी अगले दिन या उसके एक दिन बाद हो रही है। ऐसे में हम क्षमता को वास्तव में नियंत्रित करने में सक्षम हैं। ग्राहक भी हमारे प्रशंसक हैं।

राज्यों की बंदी आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, खास तौर से रविवार के जनता कर्फ्यू और उसके बाद?

केंद्र ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्य के स्तर पर उसका क्रियान्वयन रविवार को वास्तव में खराब था। हमारे कई वैन और लोगों को पुलिस ने रोका और कुछ को पीटा भी। यह उत्तर प्रदेश, मुंबई, चेन्नई और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हुआ। केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य का अभाव है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे बेहतरी का भरोसा दे रहे हैं। उन्हें भी इसका अहसास हो रहा है। हमें सरकार का सहयोग मिल रहा है।

अब इन्वेंट्री का प्रबंधन आप कैसे कर रहे हैं?

आम तौर पर हमारे पास 12 दिन की इन्वेंट्री होती है। लेकिन उसमें कमी आ रही है। साथ ही हमारे कई बड़े सप्लायर वास्तव में रोजाना आपूर्ति कर रहे हैं जबकि पहले वे दो या तीन दिन में ऐसा करते थे।

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं?

चूंकि हमें पता है कि मुश्किल वक्त में हमें काम जारी रखना है, लिहाजा यह हमारे ऊपर कई जवाबदेही भी डालता है। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारी समेत हर कोई सुरक्षित रहें। हमने हाल में संपर्कविहीन डिलिवरी पेश की है, जो डिलिवरी एजेंट व ग्राहक दोनों की सुरक्षा के लिए सही है। इसके अलावा हम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हर काम कर रहे हैं।

क्या आप सभी घर से काम कर रहे हैं?

हां, हम सभी घर से काम कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे मुख्यालय पर अभी पूरी तरह से ताला नहीं लगा है (जहां 500 लोग काम करते हैं), लेकिन करीब-करीब हम सभी अपने घर से काम कर रहे हैं। हालांकि वेयरहाउस व गोदाम खुले हैं, जो फिजिकल टच पॉइंट है।

वैश्विक प्रोत्साहन से बाजार में दिखा थोड़ा सुधार

पृष्ठ-1 का शेष

एक विश्लेषक ने कहा कि अगर वीआईएक्स सूचकांक 100 के सतर पर पहुंचता है तो इसका मतलब है कि सूचकांक दोगुना या शून्य हो सकता है। इस साल अब तक निफ्टी 35 फीसदी और सेंसेक्स 37 फीसदी नीचे आ चुका है। इसी दौरान वीआईएक्स सूचकांक 600 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है, जो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

इस बीच, वैश्विक बाजारों की तुलना में घरेलू बाजार का प्रदर्शन कमतर रहने से निवेशक निराश हैं। एसडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, 'एशियाई और यूरोपीय बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार को सबसे कम फायदा हुआ और इसका कमजोर प्रदर्शन बरकरार है।' विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकट से आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए भारी-भरकम प्रोत्साहन की जरूरत है।

विदेशी निवेशकों ने 2,153 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की और घरेलू निवेशकों ने 1,553 करोड़ रुपये की लिवाली की। बाजार में बढ़त के बावजूद सेंसेक्स मार्च में अब तक 30 फीसदी लुढ़क चुका है।

उठे आर्थिक राहत के कदम, पैकेज का आश्वासन

अरुप रॉयचौधरी और सोमेश झा
नई दिल्ली, 24 मार्च

देश में कोरोनावायरस का संकट गहराने और देश भर में बंदी झेल रहे कई कारोबारों की मुश्किलें कम करने लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आयकर दाखिल करने की मियाद 31 मार्च के बजाय तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नियामकीय और अनुपालन से जुड़े उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आम लोगों के लिए अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क नहीं लगने का ऐलान किया और साथ ही न्यूनतम बैलेंस शुल्क भी माफ कर दिया है। वहीं कंपनियों के निदेशक मंडल के साथ होने वाली अनिवार्य बैठक को भी अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों के लिए टाल दी गई है। वहीं कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 को भी लागू करना अगले एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले इसे 2019-2020 के लिए अधिसूचित किया गया था लेकिन अब इसे 2020-2021 तक लागू किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सभी हितधारकों के सुझावों पर विचार-विमर्श कर रहा था, जिनमें एक लक्षित आमदनी सहयोग योजना और व्यक्तियों तथा कंपनियों के लिए समान रूप से कर्ज भुगतान को स्थगित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें मंत्रियों, सांसदों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है और विभिन्न मुद्दों के लिए इसे उप-समूहों में बांटा गया था।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित तमाम इलाकों में कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। मंगलवार को मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव इलाके में सन्नाटे के बीच निगरानी में खड़ा जवान *फोटो-पीटीआई*

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस

सीतारमण ने कहा, 'हम एक आर्थिक पैकेज तैयार करने के करीब पहुंच चुके हैं। इस पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी' वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है और उस समय तक किए जाने वाले विलंबित भुगतान पर देय ब्याज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है।

डेलॉयट इंडिया के साझेदार आलोक अग्रवाल सरकार के इस कदम को राहत देने वाला मानते हैं। उन्होंने कहा, 'यह फैसला उन सामान्य निवासी करदाताओं के लिए राहत है जिन्हें विदेशी कर जमा (एफटीसी) लेने के लिए संशोधित कर रिटर्न जमा करने की जरूरत है।'

इस कदम ने सभी वैधानिक दायित्वों की समयसीमा को अपने-आप बढ़ा दिया है। मसलन, कर आकलन, टैक्स नोटिस भेजना, रिटर्न की प्रोसेसिंग, जुर्माना लगाने की कवायद, नए सिरे से आकलन। इसके अलावा संपत्ति कर अधिनियम, बेनामी संपत्ति अधिनियम, काला धन अधिनियम, प्रतिभूति लेनदेन कर एवं कमोडिटी लेनदेन अधिनियम के तहत कार्रवाई की समयसीमा भी बढ़कर 30 जून हो गई है।

सरकार की ओर से उठाए गए कुछ कदम

- 30 जून तक चौबीसो घंटे की कस्टम क्लियरेंस सेवा, कंपोजिशन स्कीम चुनने की तारीख को जून के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया गया
- एमसीए-21 के तहत जरूरी कोई भी दस्तावेज, रिटर्न एवं बयान 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के दौरान दाखिल किए जाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा
- स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी के बगैर कम-से-कम एक बैठक से अलग रखा गया

आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए तय की गई 31 मार्च की समयसीमा और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना का दायरा 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत दी गई वह सुविधा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है जिसमें 31 मार्च तक भुगतान करने पर 10 फीसदी अतिरिक्त राशि नहीं देने का प्रावधान रखा गया था।

वित्त मंत्री ने कहा, 'अग्रिम कर, स्व-आकलन कर, सामान्य कर, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के 20 मार्च से 30 जून के बीच होने वाले विलंबित भुगतान पर देय ब्याज दर को भी 12-18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया गया है। इस दौरान होने वाले भुगतान पर कोई लेट फी और जुर्माना भी नहीं लगेगा।' विवाद से विश्वास योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए समयसीमा में की गई बढ़ोतरी को कर विशेषज्ञों ने सराहा है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के कर एवं नियामकीय साझेदार विक्रम दोषी कहते हैं, 'इससे करदाताओं को इस समाधान योजना का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर मिल सकेगा।'

इसी तरह खेतान ऐंड कंपनी के साझेदार अभिषेक रस्तोगी कहते हैं कि इस कदम से कारोबारी प्रतिष्ठान बढ़े हुए समय में लंबित मुकदमों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सीतारमण ने यह भी कहा कि पांच करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबार मार्च से लेकर मई तक का जीएसटी रिटर्न जून के आखिरी सप्ताह तक दाखिल कर सकते हैं। उन पर किसी तरह का विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज भी लगेगा। वहीं इस श्रेणी से बाहर के कारोबारियों पर नौ फीसदी की घटी दर से ब्याज लगेगा। वित्त मंत्री से जब कोविड-19 की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के आर्थिक वृद्धि पर संभावित असर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ खुलकर नहीं कहा। उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने सार्वभौम बुनियादी आय योजना लाने से लेकर कंपनियों एवं व्यक्तियों की किस्तें स्थगित करने के बारे में सुझाव दिए हैं। हम इन बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। जल्द ही आपको कुछ सुनने को मिलेगा।'

(श्रीमी चौधरी, दिलाशा सेठ और रुचिका चित्रवंशी का भी योगदान)

केंद्र ने दिए निर्माण मजदूरों को धन देने के निर्देश

सोमेश झा
नई दिल्ली, 24 मार्च

असंगठित क्षेत्र को राहत देने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज राज्यों को निर्देश दिया है कि जनकल्याण कोषों के इस्तेमाल न हुए धन का इस्तेमाल निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के बैंक खातों में हस्तांतरित करें। कोविड-19 के कारण हुई नाकेबंदी की वजह से मजदूरों के संकट को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाए हैं।

इसके अलावा सरकार ने नियोक्ताओं को भी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय कानूनों के तहत 2019 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दी है। मुख्य केंद्रीय श्रम आयुक्त की ओर से 20 मार्च को जारी पत्र में कहा गया है कि वैश्विक महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर प्रतिष्ठान फरवरी के अंत तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे भवन व अन्य निर्माण कामगारों के कल्याण उपकर कोष के 52,000 करोड़ रुपये राशि का इस्तेमाल करें। देश में करीब 3.5 करोड़ निर्माण मजदूर हैं, जो बिल्डिंग ऐंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्ल्यू) वेलफेयर सेस ऐक्ट 1996 के तहत पंजीकृत हैं। उपकर कोष का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं, जो अपने इलाके के निर्माण मजदूरों के रजिस्टर को भी अद्यतन करती हैं। निर्माण मजदूरों से जुड़ी मेडिकल सहायता, पेंशन, मकान बनाने के लिए कर्ज, बीमा, उनके बच्चों की शिक्षा, मातृत्व लाभ के अलावा अन्य सुविधाओं की योजना राज्य सरकारें बनाती हैं। बहरहाल तमाम राज्य सरकारों ने इस धन का उपयोग नहीं किया है और इसके लिए उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य सरकारों की खिंचाई भी कर चुका है।

सरकार ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए अधिनियम की धारा 60 का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है कि वे 'योजना तैयार करके निर्माण कर्मचारियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पर्याप्त धन का हस्तांतरण करें।' दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य सरकारें केंद्र का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं।

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, 'निर्माण मजदूरों को जारी की जाने वाली राशि के संबंध में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कर सकते हैं। इस मोड़ पर वित्तीय सहायता से हमारे निर्माण कर्मचारियों को हुए आर्थिक संकट को आंशिक रूप से कम किया जा सकता है। इससे महामारी से लड़ने को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।'

नई रणनीति

- लॉकडाउन के कारण मजदूरों की सहायता के लिए जनकल्याण कोष के धन का हस्तांतरण सीधे मजदूरों के खाते में करने के निर्देश
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों के खाते में 5000 रुपये डालने की घोषणा की
- पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इस मद से निर्माण मजदूरों को 3,000 रुपये देने की कर चुके हैं घोषणा

केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के तत्काल बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपये नकदी हस्तांतरण की घोषणा की है।

श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में करीब 5 करोड़ निर्माण मजदूर हैं और इस अधिनियम के तहत ज्यादा कामगारों को पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकारें अभियान चला सकती हैं, जिससे जिन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो सका है, उन्हें भी नकदी अंतरण का लाभ मिल सके। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही उपकर का इस्तेमाल कर कर्मचारियों को राहत देने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हर पंजीकृत निर्माण मजदूर को तत्काल 3,000 रुपये की राहत देने की घोषणा की है। वहीं हिमाचल प्रदेश भी इस तरह के मजदूरों को तत्काल एकमुश्त 1,000 रुपये देगा।

यूपी सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 24 मार्च

कोरोना महामारी के चलते तालाबंदी में जीविका गंवाने वाले 20 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है।

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अपने जिलों में लोगों का आवागमन रोकने के लिए कर्फ्यू भी लगाएं। बुधवार से लेकर 27 मार्च तक पूरा उत्तर प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। कोरोना को लेकर फेक न्यूज पर भी योगी सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर विभिन्न सभी पेंशनधारकों को 3 महीने की एडवांस पेंशन मिलेगी।

आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपये की पहली किस्त डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में भेज दी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के खिलाफ सबको सहभागी बनाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने दैनिक श्रमिकों के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदारों को भी 1000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता दे रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने आवास से श्रमिक भरण-पोषण योजना की शुरुआत की।

बंदी से रियल्टी परियोजनाओं में होगी देरी

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 24 मार्च

लॉकडाउन के कारण प्रॉपर्टी परियोजनाओं के निर्माण पर लगी रोक की वजह से परियोजनाओं में देरी होगी और इसका आगामी त्योहारी में बिक्री पर असर पड़ेगा। आज जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ने कहा, 'देश के 7 प्रमुख शहरों में 2013 से 2019 के बीच शुरू हुई 15.62 लाख से ज्यादा फ्लैट निर्माणाधीन हैं।' इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ही करीब 57 प्रतिशत यानी 8.9 लाख फ्लैट हैं।

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के शोध प्रमुख और निदेशक प्रशांत ठाकुर ने कहा, 'इन दोनों क्षेत्रों (एमएमआर और एनसीआर) में पहले ही लाखों फ्लैट पर देरी से काम चल रहे हैं। निर्माण गतिविधियां करीब रुक गई हैं। मकान के खरीदार अभी घरों में हैं। इसकी वजह से परियोजनाओं की डिलिवरी में अभी और देरी होगी।'

ठाकुर ने कहा कि डेवलपरों ने आगामी त्योहारों गुडी पडवा, अक्षय तृतीया, नवरात्रि और उगाडी को देखते हुए डेवलपरों ने परियोजनाएं पेश करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, 'शहरों में लॉकडाउन के कड़े निर्देश की वजह से आगामी त्योहारी सीजन में हाउसिंग की बिक्री प्रभावित होगी, खासकर वे खरीदार मकान नहीं खरीद पाएंगे, जो त्योहार के दिन लेना चाहते हैं।'

- एनारॉक प्रॉपर्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण 15.62 लाख निर्माणाधीन परियोजनाओं की डिलिवरी में होगी देरी
- मुंबई के डेवलपरों रुस्तमजी, सनटेक रियल्टी का भी मानना है कि इस आपदा ने रोक दिया है काम
- इंडिया रेटिंग के मुताबिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पड़ रहा वैश्विक आपदा कोरोनावायरस की बंदी का असर

डेवलपर इस रिपोर्ट से सहमत हैं। मुंबई स्थित सनटेक रियल्टी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कमल खेतान ने कहा कि निर्माण रुक जाने की वजह से परियोजनाओं में देरी होगी। खेतान ने कहा, 'हमने कर्मचारियों की जिंदगी व स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए साइट पर काम बंद कर दिया है। हमने ठेकेदारों से कहा है कि मजदूरों को खाना और मजदूरी दी जाए।'

लॉकडाउन के पहले सनटेक का मुंबई की 9-10 परियोजनाओं पर काम चल रहा था।

रुस्तमजी के चेयरमैन बोमन ईरानी ने कहा, 'परियोजनाओं में देरी होगी, लेकिन इस पर बात करने का यह सही वक्त नहीं है। हम इस वैश्विक आपदा से लड़ेंगे और लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।'

बहरहाल ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन विकास ओबेरॉय का कहना है कि कंपनी की परियोजनाओं में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'हम अपने काम पूरा करने के लक्ष्य से आगे चल रहे हैं और हमारी करीब सभी परियोजनाओं के मामले में पर्याप्त समय है।' उन्होंने कहा कि हमारी कामना है कि सब कुछ अच्छा हो और प्रार्थना करते हैं कि जल्द कोई समाधान निकले।

रेटिंग फर्म इंडिया रेटिंग ऐंड रिसर्च ने आज कहा कि लॉकडाउन की वजह से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू करने में व्यवधान आएगा। एजेंसी ने कहा, 'इससे कम अवधि के हिसाब से निर्माण कंपनियों की राजस्व वृद्धि घटेगी।'

बीएस सूडोकू 3697 | परिणाम संख्या 3696

	8	5	6				2	
						4		9
9				5	2			7
				6	5			
	5	8				6	3	
			3	2				
5			9	1				2
6		9						
	1				3	5	9	

2	9	7	5	8	4	6	1	3
4	3	5	1	6	7	9	8	2
8	1	6	3	9	2	5	7	4
9	6	4	8	1	3	7	2	5
7	8	2	9	4	5	3	6	1
1	5	3	7	2	6	8	4	9
3	4	9	6	7	1	2	5	8
6	2	8	4	5	9	1	3	7
5	7	1	2	3	8	4	9	6

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम

★★★☆☆

मंडी में गिरी फल और सब्जियों की बिक्री

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 24 मार्च

कोरोनावायरस की मार सब्जियों के कारोबार पर पड़ रही है। दिल्ली की मंडियों में खरीदार कम आने और सब्जियों की बाहरी राज्यों को आपूर्ति बाधित होने से इनकी बिक्री में भारी कमी देखी जा रही है। बिक्री गिरने से सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है। कुछ दिन पहले महंगे बिकने वाले आलू-प्याज भी अब सस्ते हो गए हैं। कारोबार में गिरावट से कारोबारियों में मंडी बंद करने की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी मंडी कारोबारी और प्रशासन मंडी बंद नहीं करने की बात कह रहे हैं। कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी आजादपुर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आजादपुर मंडी से दिल्ली के पडोसी राज्यों को आपूर्ति की जाती है। दिल्ली में फल-सब्जियों की भरी गाड़ी तो आने दे रहे हैं, लेकिन खाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। सब्जी के मंडी से बाहर न जाने के कारण इनकी बिक्री में 50 से 60 फीसदी गिरावट आ चुकी है। बिक्री गिरने से इनके दाम भी कम हुए हैं। पिछले सप्ताह मांग बढ़ने से महंगे हुए आलू-प्याज के दाम भी अब गिर चुके हैं। 1500 से 2500 रुपये बिकने वाला प्याज अब 1000 से 1750 रुपये क्विंटल बिक रहा है। आलू के दाम 1100 से 1800 रुपये से घटकर 1000 से 1600 रुपये क्विंटल रह गए हैं। आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी बलवीर सिंह कहते हैं कि 350 रुपये में बिकने वाली टमाटर 25 किलो अब 250 रुपये में मिल रही है। चैंबर आफ फ्रूट ऐंड वेजिटेवल आजादपुर के महासचिव और फल कारोबारी राजकुमार भाटिया ने बताया कि आजादपुर में उत्पादक राज्यों से फल की बडे पैमाने पर आपूर्ति होती हैं और यहां से दूसरे राज्यों को भी इसकी आपूर्ति की जाती है। खाली गाडियों पर बंदिश से इसकी बाहरी राज्यों को आपूर्ति न होने से बिक्री घटी है और दाम भी कम हुए हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 32

नेक इरादा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐसे कई उपायों की घोषणा की जो कई तरह के भुगतान या नियमन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नोवल कोरोनावायरस से निपटने के लिए हो रहे लॉकडाउन के कारण करदाताओं और कंपनियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। व्यापक तौर पर सीतारमण ने प्रक्रियात्मक कदमों की घोषणा की लेकिन इनसे करदाताओं और कंपनियों को एक समान राहत मिलेगी। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आय कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए भी ऐसा ही किया गया है। कर जमा करने में होने वाली देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर भी कम की गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भी ऐसे ही उपाय किए गए। छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए ब्याज और जुर्माने से रियायत की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई।

सीतारमण ने स्पष्ट कहा कि यह सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला आर्थिक पैकेज नहीं है बल्कि सांविधिक और नियामकीय अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर एक घोषणा भर है। चाहे जो भी हो लेकिन ये कदम आवश्यक थे और ऐसे समय में ये कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं। सरकार आगे और कदम उठाने को तैयार है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। यह ऐसे समय में हुआ जब पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है। 30 राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के साथ करीब-करीब पूरा देश थम सा गया है। कंपनियों पर इसका गहरा असर होगा। खासतौर पर उन कंपनियों पर जो कम मार्जिन पर और न्यूनतम कार्यशील पूंजी के साथ काम करती हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियामकीय अनुपालन के कारण उन पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। यह सुनिश्चित करना भी अहम है। इस अवधि में कंपनियों के दिवालिया होने का कोई बड़ा मामला सामने न आए। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा चिंता की बात होगी। यही कारण है कि सरकार ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने की सीमा को 100 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार हमेशा से राजस्व बढ़ाने और भारतीय उत्पादकों से अधिकतम राशि जुटाने के मामले में दुविधा में रही है। खासतौर पर वह कर संग्रह की कमी से जूझती रही है और कहा जा सकता है कि उसने अक्सर उत्पादकों को मंदी से बचाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है। अब जबकि यह अप्रत्याशित संकट हमारे सामने है तो अच्छी बात है कि ऐसी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन आगे चलकर इन कदमों के पीछे की मूल भावना पर भी अमल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी मशीनरी को भविष्य में राजस्व हित के बजाय देश हित को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए। क्योंकि राजस्व को लेकर ज्यादा सोचने का असर कारोबारी माहौल पर पड़ता है। चाहे जो भी हो इस वक्त राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर ज्यादा पिछड़ना ठीक नहीं होगा। अन्य देशों ने कुछ क्षेत्रों के लिए कर रियायत की घोषणा करने के साथ-साथ इस बंदी से ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रित ऋण की घोषणा भी की है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण और आर्थिक पैकेज के साथ-साथ नियामकीय प्रतिक्रिया में इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोनावायरस संकट बहुत बुरा है। देश के कड़े नियमन और अफसरशाही के कारण इसे और बुरा नहीं बनने देना चाहिए। वित्त मंत्री का इरादा नेक है और इसे लागू किया जाना चाहिए। मंगलवार को घोषित पैकेज के अलावा देश व्यापक आर्थिक पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि यह पैकेज भी जल्दी आएगा।

अजय मोहंती

वस्तु एवं सेवा कर की दुविधा

जीएसटी के डिजाइन का ढांचा और कर वंचना प्रतिकूल चुनौतियां पेश करते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **पार्थसारथि शोम**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की जमीनी हकीकत यह है कि एक ओर तो कर वंचना हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं। पहली बात तो यह कि कर प्रशासन कर वंचना समाप्त करने के लिए सख्त बुनियादी ढांचा मुहैया कराने का वादा नहीं निभा पाया। दूसरा, प्रशासन और करदाताओं को नीति निर्माताओं द्वारा जीएसटी दरों में निरंतर बदलाव से तालमेल बिठाना पड़ता है। तीसरा, अन्य क्षेत्रों के नए कानून जीएसटी क्रियान्वयन से टकराहट वाले रहे हैं। चौथा, बड़े कारोबार भी कर वंचना को लेकर उतने ही जोखिम में होते हैं जितने कि छोटे, इससे करों को लेकर एक किस्म का विरोधाभास उत्पन्न होता है। पांचवां, व्यवस्थित कर्मियों का परीक्षण करने और उनमें उचित सुधार की कमी है।

शायद प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ी चुनौती एक कर स्वरूप से दूसरे में सूचनाओं का स्वत: संचार नहीं हो पाना भी है, हालांकि यह सफलता के लिए आवश्यक है। तकनीकी ब्योरों के अभाव में मोटे तौर पर जीएसटी के तीन स्वरूप हैं- 1एम, 2ए और 3बी। इन्हें हम अपनी सुविधा के लिए 1, 2 और 3 पुकारेंगे। करदाताओं को अपनी बिक्री का ब्योरा फॉर्म 1 में देना होता है जहां हर पंक्ति एक बिक्री दर्शाती है। इस फॉर्म में शामिल कॉलम जीएसटी क्रमांक, जारी इनवॉइस के ब्योरों, लागू जीएसटी दर, केंद्रीय जीएसटी मूल्य/राशि, राज्य जीएसटी मूल्य/राशि आदि को दर्शाते हैं। जब सीजीएसटी और एसजीएसटी को समेकित किया जाता है तो उक्त करदाता द्वारा केंद्र या राज्य के लिए जुटाया गया कुल कर संग्रह सामने आता है।

फॉर्म 2 करदाता द्वारा की गई खरीदारी दर्शाता है। यहां भी हर पंक्ति एक खरीद का प्रतिनिधित्व करती है और कॉलम जीएसटी क्रमांक, प्राप्त इनवॉइस की विस्तृत जानकारी, चुकता कर की दर और चुकता सीजीएसटी और एसजीएसटी का मूल्य दर्शाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉलम के प्रतिफल को एक साथ मिलाने से करदाताओं द्वारा खरीद पर चुकता सीजीएसटी या एसजीएसटी का मोल सामने आता है। अहम बात यह है कि इस राशि में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) शामिल होता है जिसे कर चुकाने वाले वापस प्राप्त कर सकते हैं।

फॉर्म 3 जीएसटी रिटर्न से संबंधित है। यह कॉलम कर जवाबदेही दर्शाता है, यह कुल बिक्री से हासिल कर में से खरीद पर चुकता कर को घटाकर हासिल होती है। अतिरिक्त कॉलम दर्शाता है कि कितना कर नकदी के रूप में जमा किया गया और कितना समेकित क्रेडिट (ऐसी) के रूप में। ऐसी को एक अलग इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दर्शाया जाता है जो यह बताता है कि कितना कर नकदी में चुकाया गया और कितना आईटीसी के माध्यम से।

जीएसटी की दुविधा

यदि उत्पादन मूल्य कच्चे माल की लागत से अधिक है (जैसा कि अक्सर होता है) तो यह आशा की जा सकती है कि कच्चे माल पर चुकता कर, उत्पादन पर चुकाए जाने वाले कर से कम होगा। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। उत्पादन पर लगने वाले जीएसटी की दर कच्चे माल से कम भी हो सकती है। एक बड़ी कमी यह है कि फॉर्म 1, 2 और तीन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जोड़ा जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म 3 को उसी समय इलेक्ट्रॉनिक ढंग से स्वचालित हो जाना था जब किसी कर दाता का जीएसटी नंबर फॉर्म 1 या फॉर्म 2 में डाला जाता। आदर्श रूप में देखा जाए तो एक करदाता के लिए तीन अलग-अलग फॉर्म में जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परंतु निजी-सार्वजनिक भागीदारी के द्वारा भी यही हो रहा है। फिलहाल इसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का ध्यान रखा जा रहा है। अपेक्षा थी कि उसे ऐसे तैयार किया जाएगा कि वह फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक अंत: संबंधों का ध्यान रखेगा। इस बुनियादी जुड़ाव वाले ढांचे के जीएसटी लागू करना अब कर वंचना से जूझने की वजह बन रहा है।

अनिवार्य तौर पर बिना लिंकेज के नवाचार के जीएसटी की व्यवस्था देश की पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से बहुत अलग नहीं थी। इसी प्रकार जीएसटी के अधीन भी कर वंचना की प्रक्रिया जारी रही। कर वंचना का एक तरीका रहा ऐसी के माध्यम से भारी भरकम कर भुगतान राशि का दावा करना। बिना जमीनी जांच के यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि इस बारे में सही दावा किया जा रहा है अथवा नहीं। लातिन अमेरिका के एक वित्त मंत्री ने एक बार मेरे समक्ष यह स्वीकार किया था कि उनके देश में अनेक हाथी चूहों के पीछे छिपे हुए हैं। जाहिर है कई बड़ी कंपनियां ऐसे ऐसी तैयार करती हैं जिनके जरिये कर चुकाया जाता है। इनमें से कुछ वैध हो सकती हैं जो दर्शाता है कि जीएसटी में ढांचागत कमियां हैं। परंतु पूरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।

दूसरा तरीका है व्यापक और गलत टर्नओवर दर्शाने का तथा इसके साथ व्यापक इनपुट कॉस्ट जोड़ने का। इससे तीन काम सिद्ध होते हैं: पहला अंशधारकों को संतुष्ट करना, दूसरा बड़े ऋण चाहने वाले कर्जदारों को संतुष्ट करना और कागज पर ऐसी तैयार करना। ऐसा तब जबकि वास्तविक खरीद-बिक्री अत्यंत कम होती है। गलत ऐसी जीएसटी के नकद राजस्व संग्रह को सीमित कर देता है। इससे सरकारी व्यय वितरण में बाधा उत्पन्न होती है और कर संग्राहकों पर संग्रह का दबाव बढ़ता है। इससे ईमानदार करदाताओं के वैध आईटीसी दावों पर सवाल उठता है।

कुछ ब्रोकरों द्वारा फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल भी किया गया। इनका इस्तेमाल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ये ब्रोकर कंपनी की जानकारी के बिना उन कारोबारों से पैसे कमाते हैं जिनकी उन्हें सेवा करनी होती है। दिवालिया संहिता से भी मदद नहीं मिली। यह करदाताओं को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में अनुच्छेद 13 का लाभ लेने का अवसर देता है। एक बार इसकी इजाजत मिल जाने के बाद जीएसटी के अधीन कर जवाबदेही हाशिये पर चली जाती है।

दूसरी ओर, जीएसटी वेबसाइट में अपलोडिंग के दौरान निरंतर समस्याएं आती रही हैं। यदि अच्छे करदाताओं से अनुपालन की अपेक्षा है तो इन कमियों को तत्काल दूर करना होगा। किसी आपूर्तिकर्ता के बाहर जाने पर जीएसटी पंजीयन को स्वत: समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो अच्छे जीएसटी करदाताओं की राह में बाधा उत्पन्न करती हैं।

अंतत: जीएसटी का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि कर चुकाने को लेकर भारतीय करदाताओं का रुख कैसा है। परंतु अनुपूरक नीति और प्रशासनिक कदमों की भी आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को एक निरंतरतापूर्ण और स्थायी कर ढांचा बनाना चाहिए। बिना किसी देरी के फॉर्मों के लिए पीपीपी मॉडल लागू किया जाना चाहिए और प्रशासन द्वारा रीफंड सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। प्रशासन को राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए पंजीयन समाप्त करने तथा अन्य कदमों से बचना चाहिए। केवल तभी जीएसटी को सफल माना जा सकता है।

औचक परीक्षण से ही लग पाएगा सामुदायिक प्रसार का पता

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

जब भी कोविड-19 जैसी महामारी आती है तो नीति-निर्माताओं को परीक्षण किट, दवाएं, अस्पतालों के बिस्तर और वेंटिलेटर जैसे प्रमुख संसाधनों के आवंटन का सबसे कारगर तरीका ही अपनाना चाहिए। उन्हें इस गंभीर बीमारी के संभावित प्रसार का भी अंदाजा लगाना होता है ताकि यह तय किया जा सके कि किसी इलाके में पूर्ण बंदी कब करनी है और आपातकालीन राजकोषीय एवं मौद्रिक कदम क्या हो सकते हैं?

इन नतीजों तक पहुंचने में आंकड़ों की भूमिका अहम होती है और सरकार का नियमित तौर पर असत्य बोलना समस्या को बढ़ा देता है। आधिकारिक आंकड़े संक्रमण एवं बीमारी से होने वाली मौतों के बारे में वास्तविक स्थिति नहीं बताते हैं लेकिन महामारी-विशेषज्ञ किसी महामारी को आंकने के लिए गणितीय तकनीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश महामारियों को अमूमन 'घातांकी' घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि एक निश्चित आधार स्तर तक संक्रमण फैल जाने के बाद संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त तेजी आएगी और महामारी पर काबू न पाए जाने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। घातांक के अनौपचारिक इस्तेमाल से गणितीय समझ धुंधली हो सकती है। संक्रमणों की संख्या 'घातांकीय' स्तर पर न होते हुए भी बढ़ सकती है और संक्रमणों की संख्या दूसरे गणितीय प्रकार्यों से निर्धारित हो सकती है।

चरघातांकी वक्र की स्थिति तब बनती है जब एक आधार संख्या का गुणन खुद से ही कई बार होता है। मसलन, कोई संक्रमित व्यक्ति चीन के वुहान से लौटकर दिल्ली आया है। फिर वह दो लोगों को संक्रमित करता है और ये दोनों लोग दो-दो अन्य लोगों को संक्रमित करते है। पहला चरण एक से शुरू होता है और फिर दो, फिर चार, फिर आठ और इसी तरह बढ़ते हुए 14वें चरण में 16,384 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। किसी महामारी का पहला चरण इसी तरह से आगे बढ़ता नजर आता है। जैसे ही महामारी पर काबू पा लिया जाता है, यह वक्र घातांकीय नहीं रह जाता है और संक्रमण स्तर सीमित हो जाता है। इस 'वक्र को समतल करने' की लोकप्रिय उक्ति का मतलब यही है कि किसी भी तरह से महामारी की प्रसार दर पर काबू पाया जाए।

एक अहम गणितीय तकनीक में संक्रामक बीमारी का परीक्षण करते समय सामाजिक नेटवर्क का मूल्यांकन भी शामिल है। निश्चित रूप से पहले संक्रमित व्यक्ति के संपर्कों की पहचान करने और उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करना जरूरी है। यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने वाले परिवार, सहकर्मियों, घरेलू कामगार, पड़ोसियों एवं दोस्तों को चिह्नित किया जा सके। लेकिन परीक्षण में आबादी के बड़े हिस्से में से औचक नमूने भी शामिल किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों को परीक्षण के लिए बिना किसी क्रम के उन लोगों को चुनने की जरूरत है जो किसी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों। पता लगाया जाए कि महामारी का सामुदायिक प्रसार तो नहीं हुआ है। मान लीजिए, एक बीमार शख्स ने बस या विमान में सफर किया है या किसी धार्मिक समारोह में शामिल हुआ है और एक अनजान शख्स को संक्रमित कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन केवल बीमार के संपर्कों का ही परीक्षण करेगा तो सामुदायिक प्रसार के बारे में पता नहीं चल पाएगा। औचक नमूनों के परीक्षण से ही सामुदायिक प्रसार को परखा जा सकता है। चीन और दक्षिण कोरिया ने भी अपने यहां संक्रमितों की शिनाख्त के लिए औचक नमूना परीक्षण का ही तरीका अपनाया है।

अधिकतर लोग 'छोटी दुनिया' नेटवर्क से ही जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया काफी हद तक अपने परिवार, दोस्तों एवं पेशेवर सहकर्मियों से बनती है और इनमें से लगभग सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। फेसबुक का कोई भी उपयोगकर्ता यह बात समझता है कि उसके एवं उसके किसी दोस्त के बीच के साझा दोस्तों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही 'छोटी दुनिया' नेटवर्क का हिस्सा हैं।

आपके कुछ ऐसे जानकार भी हो सकते हैं जो किसी दूसरी छोटी दुनिया का हिस्सा हैं। मसलन, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के चचेरे भाई से शादी में मिले थे लेकिन उसके साथ भी आपका एक दोस्त साझा है। इस तरह उसके पास आपकी छोटी दुनिया में घुसने का एक जरिया आप हैं। हालांकि खुद उसके पास अपनी अलग छोटी दुनिया मौजूद है।

इस तरह छोटी दुनिया नेटवर्क में विभिन्न आंतरिक संपर्क होते हैं और दूसरी छोटी दुनिया नेटवर्क में जाने के बेहद थोड़े लिंक होते हैं। इसका मतलब है कि अपनी छोटी दुनिया से बाहर के व्यक्ति से संक्रमित होने की आशंका अपने ही नेटवर्क में संक्रमित होने से काफी कम होती है। अगर आपके दोस्त का चचेरा भाई संक्रमित है तो उससे आपके संक्रमित होने की आशंका बेहद कम है। इसमें एक अहम गणितीय निहितार्थ भी है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो उसकी छोटी दुनिया नेटवर्क में हरेक के संक्रमित न होने तक घातांकीय वृद्धि की पूरी आशंका है। लेकिन अगर दूसरी छोटी दुनिया नेटवर्कों से आपका कोई नाता नहीं है तो फिर संक्रमण बहुत जल्द सीमित हो जाता है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विमान, मॉल, सिनेमाघरों, धार्मिक समारोहों को बंद करना अलग-अलग छोटी दुनिया के बीच संपर्क काटने की ही कवायद है। वैसे व्यापक बंदी के व्यापक निहितार्थ होते हैं, लिहाजा किसी भी सरकार को बहुत सोच-समझकर इसे लागू करना चाहिए।

कुछ शोधपत्रों में यह कहा गया है कि छोटी दुनिया की संकल्पना कोविड-19 के मामले में काम कर रही है लेकिन इसकी पुष्टि के लिए समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो औचक परीक्षणों के अभाव में हमें यह पता ही नहीं है कि कोरोना का सामुदायिक प्रसार किस हद तक है? इतना जरूर है कि सब कुछ बंद किए जाने से महामारी पर जल्द काबू पाया जा सकता है, भले ही उसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़े।

कानाफूसी

कोरोनावायरस का असर

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण संसद के बजट सत्र को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। यही कारण है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य सभा के 50 सदस्यों को दी जाने वाली औपचारिक विदाई का कार्यक्रम भी नहीं हो सका। पारंपरिक रूप से ऐसे सांसद अपना विदाई भाषण देते हैं। परंतु सोमवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटाए जाने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं आगामी 26 मार्च को होने वाले राज्य सभा चुनाव भी टाल दिए गए हैं क्योंकि उन पर मतदान के लिए तमाम विधायकों को पंक्तिबद्ध होकर मतदान करना पड़ता। गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है तथा लोगों को घर से निकलने से मना किया जा रहा है।

विपक्ष भी आया साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के साथ-साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के उत्साहवर्द्धन की जो अपील की थी उसका असर उनके समर्थकों पर तो पड़ा ही, बल्कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी इसमें सहयोग किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने, जो मोदी के बड़े आलोचक रहे हैं, रविवार शाम अपने घर की बालकनी से तालियां बजाकर उत्साहवर्द्धन में अपना सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए देश के चिकित्सक और नर्स जिस तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं वह सराहनीय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह रोज काम करके अपना पेट पालने वाले लोगों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करे और स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पृथक्करण वार्ड स्थापित किए जाएं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव जो सन 2017 में प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार गई थीं, उन्होंने भी जनता कर्फ्यू को अपना समर्थन दिया। हालांकि सोमवार को शिव सेना ने प्रधानमंत्री के आह्वान का विरोध किया। सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि आम जनता लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस गंभीर चिंता के अवसर को उत्सव में तब्दील कर दिया।

आपका पक्ष

सामाजिक दूरी बनाना अब जरूरी

भारत जैसे विशाल घनी आबादी वाले देश के लिए कोरोनावायरस महामारी की चुनौती और भी बड़ी है। अभी हम संक्रमण के दूसरे दौर में है। हमें अपने मौजूदा संसाधनों और तैयारी से इस संक्रमण को इसी समय नियंत्रण कर लेना है। सघन आबादी के कारण संक्रमण के तीसरे दौर यानी सामुदायिक प्रसार के दौर में प्रवेश करना संभव है। विकसित देशों के मुकाबले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वे इस विशाल जनसंख्या में महामारी के प्रसार का मुकाबला कर सकें। सघन निगरानी, जांच, स्वच्छता संबंधी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना और इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों का पालन करके हम महामारी को तीसरे चरण में जाने से रोक सकते हैं। सामाजिक दूरी को अपना कर हर नागरिक इसके प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

रवींद्र प्रकाश, मुरादाबाद

मुरादाबाद में प्रशासन लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील कर रहा है -पीटीआई

जागरूकता से रुक सकती है महामारी

दुनियाभर में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस से भारत भी प्रभावित है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई एजेंसियों को सतर्क किया है। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए न केवल सतर्कता बरत रही है बल्कि दवाइयों की असरदार खुराक तैयार की गई हैं। संक्रमित मरीज के इलाज के लिए एक मानक तरीके पर काम चल रहा है। इस मानक के तहत कई तरह के एंटीरेट्रोवायरल को मिलाकर इलाज का नुस्खा बनाया जा रहा है। हमें इस तरह की महामारी से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। कोई भी महामारी जागरूक रहने पर नियंत्रित हो सकती ह

संध्या कुमारी, गोरखपुर

निजी अस्पतालों की लूट पर हो अंकुश

यह अच्छी खबर है कि देश में डॉक्टरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे यह साबित होता है कि देश के चिकित्सा सेवा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है तथा निजी अस्पतालों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे अस्पताल संचालक हैं जो मुनाफे के लिए ही इस क्षेत्र में आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके पास योग्य चिकित्सकों की कमी तथा अयोग्य चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली जाती है। इसके बावजूद भी ये लोग मरीज के परिजनों का आर्थिक शोषण करते हैं। कुछ गरीब परिवार अपनों के खोने के साथ आर्थिक रूप से कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। ऐसे मामलों में निजी अस्पतालों के संचालकों पर कार्रवाई भी नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान निजी अस्पतालों के लिए काम करने वाले एजेंट का है जो मरीज को निजी अस्पतालों तक लाते हैं। सरकार को ऐसे निजी अस्पतालों पर लगाम लगाना चाहिए। सरकारी एंबुलेंस चालक एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा निजी अस्पतालों में मरीजों के दाखिला कराने पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। यह अनिवार्य होना चाहिए कि एंबुलेंस चालक तथा आशा कार्यकर्ता दोनों ही मरीज को सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही लेकर जाएं। सरकार के इस तरह के कदम उठाने पर मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लगेगा।

विमलेंद्र मणि त्रिपाठी, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।